बाड़मेर सेक्टर में द्वितीय चरण के अधीन 146 किलोमीटर क्षेत्र में और तृतीय चरण के अधीन 120 किलोमीटर क्षेत्र में कार्य चल रहा है और इस कार्य को क्रमशः दिसम्बर, 1995 और जून, 1996 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) पश्चिमी सीमा पर आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गयी हैं।

(ii) गश्त/नाकाबंदी को गहन किया गया है।

(iii) जीपें और मोटर साईकिलें उपलब्ध कराके सीमा गश्त गहन की गयी है।

(iv) नये और अतिरिक्त निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

(v) सीमा पर सर्तकता बढ़ाने के लिए दूरबीन, गोगल, टिन-टेलिस्कोप, पी.एन.वी. दूरबीनें और हाथ से पकड़ने वाली सर्च लाईटें उपलब्ध करायी गई हैं।

(vi) नदी तटीय क्षेत्रों की गश्त के लिए बोट/मोटर-बोट उपलब्ध करायी जा रही है।

(vii) वाहनों से गश्त लगाने के लिए सीमा सड़क/रास्तों का निर्माण/विकास किया जा रहा है।

(viii) सीमा पर गहन निगरानी रखने के लिए राज्य/केन्द्रीय सतर्कता तंत्र को सुचारू बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत किया जाना

1530. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी**: क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1994 से आज तक गुजरात में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, उनका विस्तार करने और मरम्मत करने का कार्य शुरू किया गया है और गुजरात से गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसा कार्य कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ख) अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है और इस पर वास्तव में कितना धन खर्च किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 अहमदाबाद-बम्बई खंड के चुनिंदा खंडों को चौड़ा करने का कार्य 1.4.94 के बाद प्रारंभ हो चुका है। वार्षिक योजना (1995-96) में रा.रा. सं. 8 और 8 ग के चुनिंदा खंडों को चार लेन का बनाने के लिए प्रावधान है। रा.रा. 8 ग पर इस कार्य के लिए मंजूरी दे दी गई है और कार्य अभी प्रारंभ होना है। गुजरात सहित देश में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) केन्द्र सरकार विकास और रख-रखाव के लिए निधियों का आबंटन राज्य-वार करती है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव हेतु गुजरात राज्य के लिए किया गया आबंटन इस प्रकार है:-

वर्ष	विकास	रख रखाव/मरम्मत
		(लाख रु.)
1994-95	7098.00	1316.64
1995-96	4600.00 (पुल शुल्क निधिको छोड़कर)	611.50 (जून, 1995 तक)

Telephone Connections on Demand

1531. DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide telephone connections of all categories on demand by January 1997;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for making promises at Public meetings;

(c) whether Government propose to provide all other facilities of Telecommunications sector to people on demand by January 1997; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) No, Sir. The National Telecom Policy 1994 announced by the Government envisages provision of telephone connections on demand by 1997 for which investment from Private Sector is also being sought.

(c) and (d) As per National Telecom Policy, various value added services will also be promoted for investment by the Private Sector.